under IRDP has been increased and procedures decentralised.

(b) This Ministry is monitoring all the programmes by getting monthly, quarterly and annual progress reports from the State Governments. The Ministry has also adopted Area Officers approach under which senior Central Government Officers carry out field visits for regular monitoring of all the rural development programmes. The Ministry of Rural Development get concurrent valuation conducted through independent research organistions. Findings of the evauation are communicated to all the State Governments/Union Territories and they are constantly advised to be vigilant about proper implementation of the programmes to avoid wasteful expanditure. Programme is constantly under the review of the Ministry to improve its effectivaness.

Drinking Water Facilities in the Country

495. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Drinking Water Mission has completed its task and if so, what is the number of villages which are yet to be provided with drinking water;

(b) what is the State-wise number of villages which have been provided with drinking water facilities and the number of villages where the programme is fully effective and what is the number of villages where the facilities are unoperational and the reasons therefor;

(c) what is the State-wise number of villages which have been identified as having no source of water and what is being done to provide them with drinking water facilities; and

(d) by when all villages in India are likely to be fully covered by the National Drinking Water Mission?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) to (c) The Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission was set up in the year 1986 Based on the survey conducted in the year 1985 to identify problem villages (PVs) there were 161722 PVs as on 1-4-1985, out of which 24567 PVs were covered in 1985-86. Thus the main objective of the Mission was to cover the remaining 1,371 PVs, out of which 1,36,877 were covered upto 31.3.1994 details showing State-wise details of number of 'no source' villages as on 1.4.1985, number of villages which have been provided with safe drinking water facilities till 31.3.1994 and the number of villages which remained with no source of water has on 1.4.1994 are givn in Annexure No.(*See* Appendix 171, Annexure No. 12)

(d) 278 'no source' villages which remained to be covered as in 31.3.1994 are likely to be provided with at least one source of potable water by the end of 1994-95. The partially covered villages are likely to be covered fully by the end of VIII Five Year Plan.

भू-अभिलेख प्रलेखन का आधुनिकीकरण

496. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भू-प्रलेखन पद्धति को आधुनिक बनाने की दृष्टि से भू-प्रलेखों के कम्प्यूटरीकरण, राजस्व-प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए कोई योजना बनाने हेतु कार्य आरंभ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उक्त योजना को कब तक लागू कर दिये जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां। भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने और अपने

राजस्व तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के काम में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता देने के उद्देश्य से राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1987-88 से पहले ही चल रही है। इसके अतिरिक्त भू-धारकों को अपने अधिकारों की अद्यतन प्रति शीघ्र और सस्ती दर पर मिल सके, इस उद्देश्य से एक अन्य योजना अर्थात भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

(ख) और (ग) लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने की योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्यों, भू-अभिलेखों को तैयार करने, उनका रख-रखाव करने और उन्हें अद्यतन बनाने, राजस्व, सर्वेक्षण और बन्दोबस्त स्टाफ को सेवा में आने से पूर्व और सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने और इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण, ढांचे को सुदृढ़ बनाने के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए इन राज्यों को केन्द्रीय अंश के रूप में 79.84 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए अभी तक 60 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में 13.78 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की परियोजना पूरी हो चुकी है और उसने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। शेष परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है। चूंकि भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने और उनका कम्प्यूटरीकरण करने की प्रक्रिया में समय लगता है इसलिए योजनाओं के आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी जारी रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में पेय-जल की कमी

497. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भीषण सूखे के कारण उत्तर प्रदेश के गांवों में पेय-जल की अत्यधिक कमी थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त राज्य के इन गांवों में पेय-जल सुलभ कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में और अधिक कुएं खोदने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को पेयजल सुलभ कराने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बिना जल स्रोत वाले गांवों की कवरेज के लिए केन्द्र सरकार ने 1991-92 में 28.67 करोड़ रुपए तथा 1992-93 में 7.81 करोड़ रुपए की विशेष सहायता त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य आबंटन के अतिरिक्त मुहैया की थी। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य आबंटन को भी 1992-93 में 43.48 करोड़ रुपए से 1993-94 में 76.48 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया तथा 1994-95 में 86.16 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।